मौद्रिक प्रबन्धन और वित्तीय मध्यस्थता

03
अध्याय

वर्ष 2014-15 में बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में अनेक सुधार उपाय किए गए। इनमें 52 प्रतिशत तक सरकारी हिस्सा कम करके पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा करने के लिए बाजार से पूंजी जुटाने हेतु बैंकों को अनुमति देना, प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक साधारण बैंक खाते की बैंकिंग सुविधा व्यापक रूप से सुलभ करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करना और बीमा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी सीमा बढ़ाने के संबंध में अध्यादेश अधिसूचित किया जाना शामिल है। इक्विटी बाजार का अच्छा निष्पादन जारी रहा और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों के बेहतर कार्यकरण के लिए कारपोरेट अभिशासन के मानदंडों में सुधार और विदेशी परिस्थितियों संबंधी विनियमन ढांचे की स्थापना जैसे अनेक कदम सेबी ने उठाए। तथापि, वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में दबाव के कुछ संकेत देखे गए। कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल अनर्जक अग्रिमों में वर्ष के दौरान बढ़ोतरी देखी गई। इस वर्ष बैंक ऋण की वृद्धि में भी गिरावट आई।

2014-15 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

3.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत सम्प्रेषण के लिए अनुमानित स्थिरक के उपाय के रूप में नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सम्मिश्रित) को अपनाया है। वर्ष के दौरान जनवरी, 2015 तक पॉलिसी दर अपरिवर्तित रखी गई। स्फीतिकारी दबाव कम करना जारी रखने की दृष्टि से 15 जनवरी, 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी समायोजन सुविधा के अंतर्गत पॉलिसी रेपो दर घटाकर 8.0 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत किया। सारणी 3.1 तथा चित्र 3.1 में 2013-2015 तक पालिसी दरों में संशोधान तथा घट-बढ़ को दर्शाया गया है।

मौद्रिक संग्रहणों में प्रवृत्ति

3.3 2014-15 के दौरान प्रारक्षित मुद्रा (एम0) और स्थूल मुद्रा (एम3) दोनों पिछले वर्ष की तुलना में कम हुए हैं। एम0 में कमी मुख्यतया जमाराशि में वर्ष अन्त में अधिक अभिवृद्धि के कारण भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकरों की जमाराशि का समायोजनों को दर्शाती है। स्रोत पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 3.1 : पॉलिसी दर में संशोधन

प्रभावी तिथि	बैंक दर/एमएसएफ दर (प्रतिशत	रेपो दर (प्रतिशत	रिवर्स रेपो दर (प्रतिशत)	एनडीटीएल का सीआरआर (प्रतिशत)	एनडीटीएल का एसएलआर (प्रतिशत)
19-03-2013	8.50	7.50	6.50	4.00 $	
03-05-2013	8.25	7.25	6.25		
15-07-2013	10.25				
20-09-2013	9.50	7.50	6.50		
07-10-2013	9.00				
29-10-2013	8.75	7.75	6.75		
28-01-2014	9.00	8.00	7.00		
14-06-2014					22.50
09-08-2014					22.00
15-01-2015	8.75	7.75	6.75		
7-02-2015					21.50

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: * बैंक दर 13.02.2012 से एमएसएफ दर से संरेखित की गयी; $: 09.02.2013 से।

एमएसएफ-सीमांत स्थायी सुविधा; सीआरआर-प्रारक्षित नकदी अनुपात; एसएलआर-सांविधिक नकदी अनुपात; एनडीटीएल-निवल मांग तथा समय देयता।

चित्र 3.1: नीति दरों में घट-बढ़

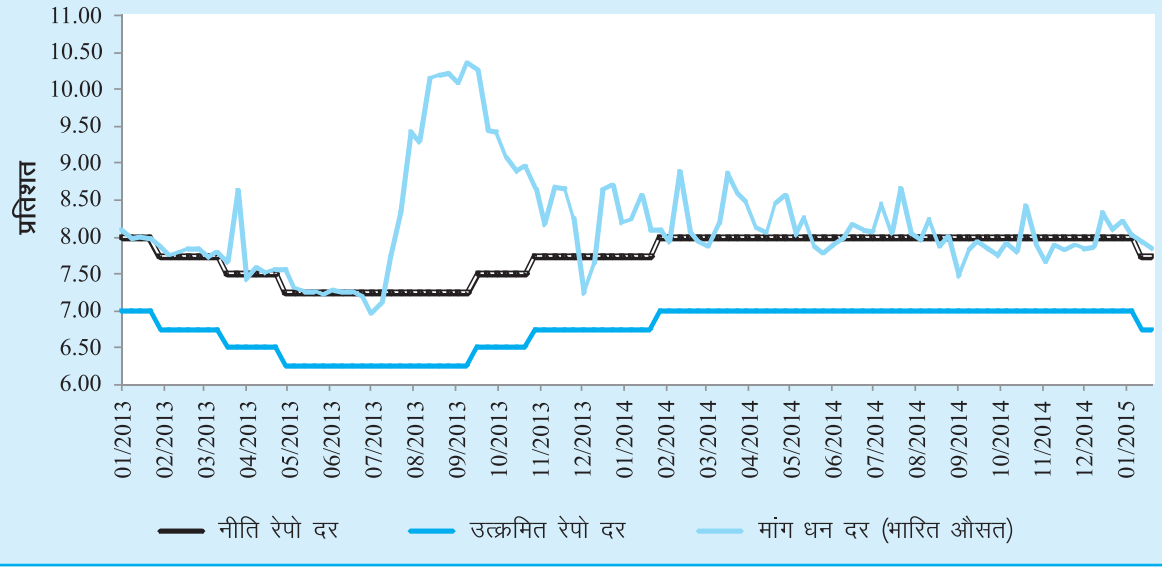

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि को अधिकांशत: एनडीए में कमी द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो नकदी की जोरदार मांग के अभाव में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम निवल नकदी अंत:क्षेपण को दर्शाता है (सारणी 3.4)। परिचलन में करेंसी का रूझान कमजोर आर्थिक क्रियाकलाप दर्शाया। (सारणी 3.2)

3.4 ऋण में गिरावट (सारणी 3.3) आर्थिक गिरावट, निधियों के वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता बैंकों और विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को कुछ बैंकों द्वारा बलित ऋणों को बेचे जाने के कारण माना जा सकता है। सरकारी विभागों और सरकारी उद्यमों द्वारा भुगतान प्राप्त करने वाले निकायों द्वारा ऋणों की अदायगी किए जाने और तेल विपणन कंपनियों द्वारा कम ऋण लेने के कारण निवल बैंक ऋण भी कम है।

नकदी प्रबंधन:

3.5 नकदी प्रबंधन प्रचलन में लचीलापन, पारदर्शिता और पूर्वानुमान योग्य संभावना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 सितंबर 2014 से अपने नकदी प्रबंधन ढांचे में संशोधन किया है। मुख्य विशेषताओं में शामिल है: (क) बैंकवार एकाएक एनडीटीएल का 0.25 प्रतिशत नियत

सारणी 3.2 : प्रारक्षित मुद्रा में परिवर्तन के स्रोत (वृद्धि प्रतिशत में)

	वित्त वर्ष		
	2013-14	31 मार्च 2013 की तुलना में 3 जनवरी 2014 को	31 मार्च 2014 की तुलना में 2 जनवरी 2015 को
आरक्षित मुद्रा	14.4	5.1	0.9
घटक			
प्रचलन में मुद्रा	9.2	5.7	5.9
भा.रि.बैं. में बैंकरों की जमाराशियां	34.0	3.3	-15.7
आरक्षित मुद्रा के चुनिंदा स्रोत			
भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	15.7	15.1	10.9
जनता के प्रति सरकार की मुद्रा संबंधी देनदारियां	13.0	15.1	8.1
भा.रि.बैं. की निवल गैर-मौद्रिक देनदारियां	21.8	26.6	0.6

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 3.3 : मुद्रा स्टॉक (एम3) में परिवर्तन के स्रोत (प्रतिशत में)

	2013-14	31 मार्च 2013 से 27 दिसम्बर 2013 तक	31 मार्च 2014 से 26 दिसम्बर 2014 तक
स्थूल मुद्रा ($एम_3$)	13.2	9.9	7.9
जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	9.4	6.4	6.2
बैंक के पास मांग जमाराशियां	6.8	2.7	7.7
बैंकों में सावधि जमाराशियां	14.6	11.4	8.2
भा.रि.बैं. के पास ''अन्य'' जमाराशियां	-39.3	-23.2	314.2
मुद्रा भंडार ($एम_3$) में परिवर्तन के स्रोत			
सरकार को प्राप्त निवल बैंक ऋण जिसमें से	12.2	9.3	1.5
सरकार के अन्य बैंक ऋण	10.5	10.2	10.1
वाणिज्यिक क्षेत्र को प्राप्त बैंक ऋण जिसमें से	13.7	9.1	5.7
वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्य बैंक ऋण	13.6	9.1	5.8
बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	17.6	16.0	9.5
जनता के प्रति सरकार की मुद्रा संबंधी देनदारियां	13.0	9.9	7.3
बैंकिंग क्षेत्र जमाराशियों के अलावा निवल मुद्रा भिन्न देनदारियां	17.4	12.3	-8.2
ज्ञापन मदें			
मुद्रा गुणक	5.5		
मुद्रा की गति	1.2		
निवल घरेलू परिसंपत्तियां	12.1	8.5	7.5
निवल घरेलू ऋण	13.2	9.2	4.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

दर रेपो और परिवर्तनीय दर 14 दिवसीय सावधि रेपों द्वारा एनडीटीएल (निर्यात - ऋण पुनर्वित्तपोषण को छोड़कर) के 1 प्रतिशत नकदी की आश्वासित सुलभता; (ख) पखवाड़े के दौरान सावधि रेपो (4 बार) की अधिक बारंबार नीलामी, बैंकों को अपना नकदी आकलन बदलने के लिए लचीलापन प्रदान करना; और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की एकाएक नकदी की सुलभता हेतु अधिक बारंबारता साथ-ही साथ परिवर्तनीय दर ओवरनाइट रेपो/प्रारक्षित रेपो नीलामी/सावधि रेपो नीलामी की परिकल्पना प्रतिरोधात्मक नकदी प्रबंधन की मुख्य लिखत के रूप में विकसित होने के रूप में की गई है।

सारणी 3.4 एनडीए और एनएफए की तिमाही अंत में वृद्धि (प्रतिशत)

	एनडीए	एनएफए
3/31/2013	9.1	5.8
6/28/2013	19.5	4.0
9/27/2013	24.9	10.6
12/27/2013	13.8	13.1
3/31/2014	18.3	15.7
6/27/2014	-2.1	12.7
9/26/2014	-21.5	13.7
12/26/2014	-19.0	11.5

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

नकदी स्थितियां

3.6 अभी तक 2014-15 के दौरान नकदी स्थितियां मोटे तौर पर संतुलित रही हैं। केवल विलंब से सरकार द्वारा व्यय किए जाने के कारण अस्थायी रूप से स्थिति तंग थी। मार्च 2014 में नकदी की स्थिति तंग थी। सरकार के पास नकदी शेष में गिरावट आने के कारण 2014-15 की पहली तिमाही से नकदी की स्थिति में सुधार आया। जमा राशि जुटाने और सरकार के पास अधिक नकद राशि का आहरण द्वारा कम किए जाने की तुलना में ऋण लेन की धीमी गति से अगस्त से नकदी दबाव कम करने में सहायता मिली। ऋण और जमाराशि की वृद्धि के बीच कम होते अन्तर (जो अगस्त, 2014 में ऋणात्मक हो गया) से भी इस अवधि के दौरान नकदी पर दबाव कम करने में सहायता मिली। संशोधित नकदी प्रबंधन ढांचा 14 दिवसीय सावधि रेपो नीलामी में

भारांशित औसत दरों की कटौती करने में सहायता किया तथा ओवरनाइट परिवर्तनीय दर रेपो नीलामियों को रेपोदर के इर्द गिर्द बनाए रखने में सहायता किया। भारांशित औसत कॉल दर की अस्थिरता कम हुई। भारांशित औसत कॉल दरों और सरकार के लिए दीर्घावधिक लाभ और अगस्त 2014 के अंत में उच्च गुणवत्तावाले कारपोरेट निर्गमों से पता चलता है कि मौद्रिक स्थिति में कुछ सहजता आयी है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार में घटनाक्रम

3.7 10 वर्ष का सरकारी बांड अधिक समय तक लाभों में कमी बेशी को दर्शाता है। 10 वर्षीय दरें सॉवरन के प्रोक्सी ऋण जोखिम भी है। लाभों में वृद्धि के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारकों में केन्द्र में नई स्थिर सरकार से आशाओं के कारण सकारात्मक बाजार का रूझान दिसंबर 2014 में तीन में सबसे

चित्र 3.2: प्राप्ति वक्र

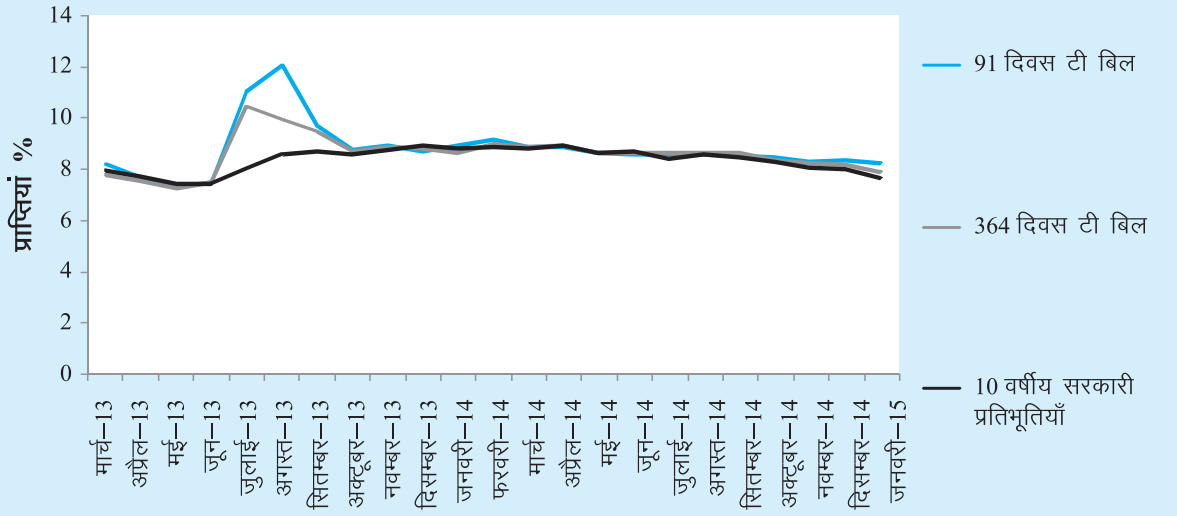

स्रोत : आरबीआई और भारतीय आर्थिक निगरानी केंद्र

चित्र 3.3: 10 वर्षीय सरकारी बांड से प्राप्ति (भारत तथा अमेरीका)

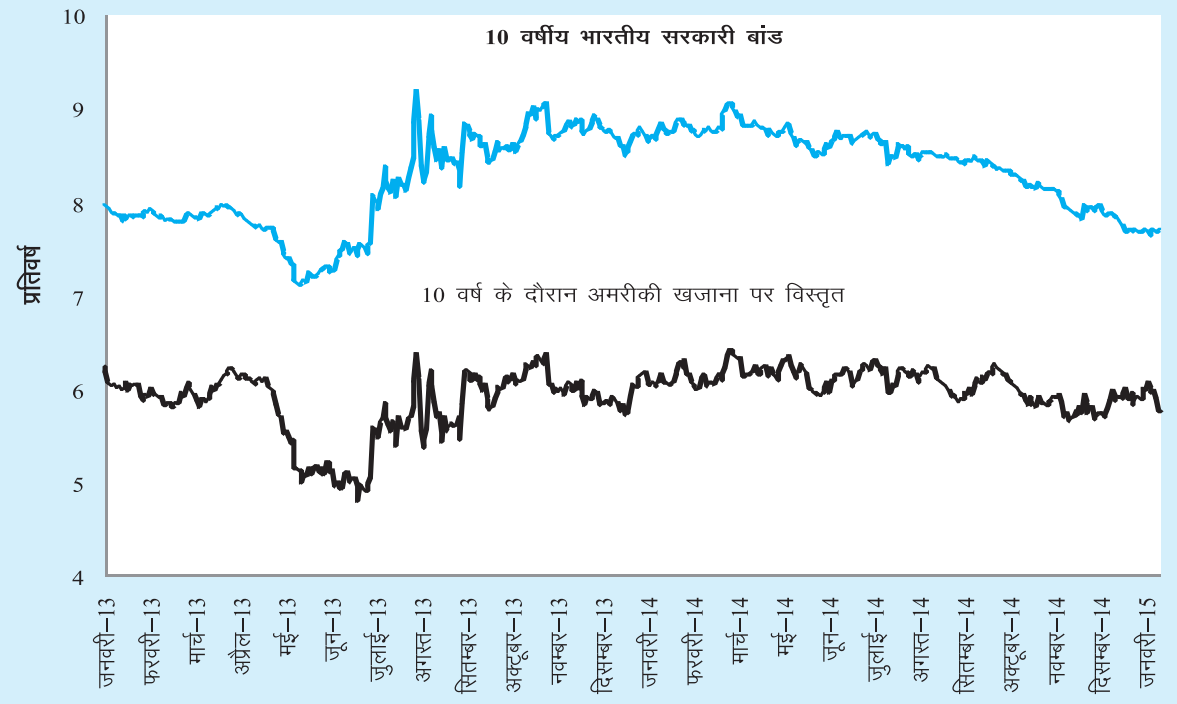

स्रोत : ब्लूमबर्ग

कम खुदरा मुद्रास्फीति रीडिंग, वस्तुओं के मूल्यों में महत्वपूर्ण सुधार और राजकोषीय मोर्चे पर सरकार द्वारा दर्शायी गई पक्की वचनबद्धता, सॉवरन ऋण निर्धारण एजेंसी एस एंड पी आदि द्वारा संभावनाएं बढ़ाना हैं। (चित्र 3.2 तथा 3.3)

सारणी 3.5 : चुनिंदा बैंकिंग जमाराशियों में वृद्धि दर

	%परिवर्तन			
	2012-13	2013-14	2013-14 (13 दिसंबर की स्थिति के अनुसार)	2014-15 (12 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार)
1. बैंक ऋण	14.1	13.9	14.6	10.9
(क) खाद्य क्षेत्र में ऋण	18.6	2.1	-1.1	-2.1
(ख) गैर-खाद्य क्षेत्र में ऋण	14.0	14.2	14.9	11.1
2. सकल जमाराशि	14.2	14.1	16.6	10.6
(क) मांग जमा	5.9	7.8	12.3	7.6
(ख) सावधि जमाराशि	15.2	14.8	17.0	10.9
3. निवेश	15.4	10.3	14.0	10.4
(क) सरकारी प्रतिभूतियां	15.5	10.4	14.0	10.5
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-11.5	-33.6	-5.8	-8.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (वर्ष 2014-15 के आंकड़े अनंतिम हैं।

बैंक ऋण

3.8 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सरल जमाराशि में वृद्धि की दर में 2014-15 के दौरान दिसंबर महीने तक कमी देखी गई (सारणी 3.5) जिसका कारण आधार प्रभाव उत्पन्न होना अर्थात गत वर्ष सितंबर-नवंबर के दौरान एनआरआई जमाराशियों में उच्च वृद्धि होना और इस वर्ष के दौरान जमाराशि का कम मात्रा में प्राप्त होना है। गैर खाद्य क्षेत्र में ऋण में भी कमी आई है। (चित्र 3.4 भी देखें)

चित्र 3.4: वाणिज्यिक क्षेत्र तथा खाद्य भिन्न ऋण के लिए बैंक ऋणों में वर्षानुवर्ष वृद्धि

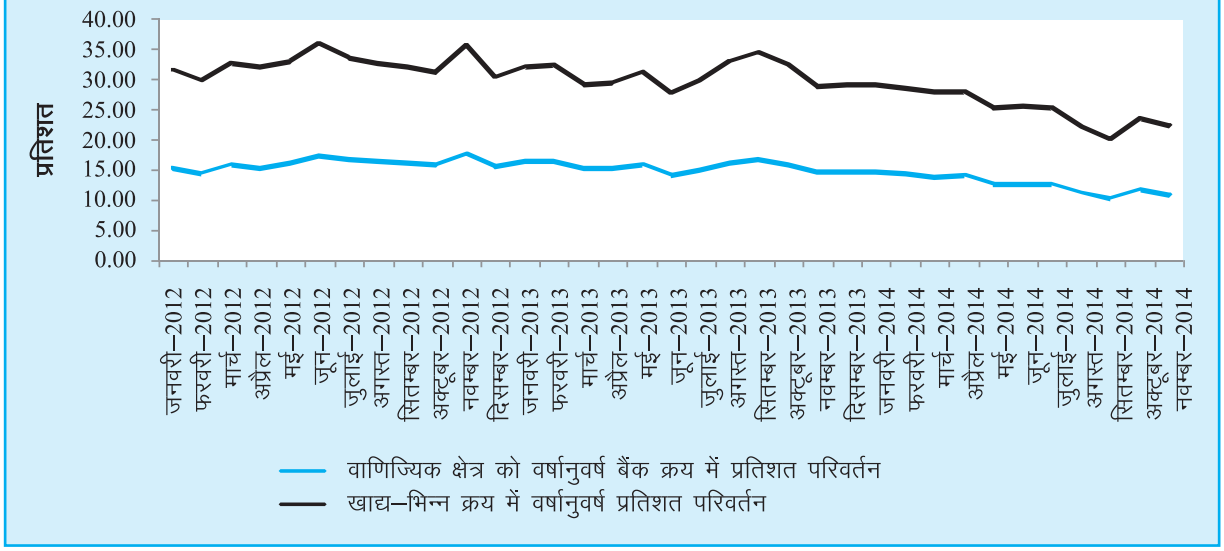

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) की ब्याज दरें

3.9 पॉलिसी दर में परिवर्तन के कारण 2014-15 में बैंकों की जमा और ऋण दरों पर प्रभाव अब तक प्रदर्शित नहीं हुआ है जो ऋण बाजार में संरचनात्मक सुदृढ़ता का मौजूदा होना, बैंकों की दुर्बल मूल्य-निर्धारण क्षमता तथा आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान दिसंबर तक सभी परिपक्वता राशियों के संदर्भ में बैंकों की औसत मासिक जमा दरों में मामूली कमी आई (सारणी 3.6), जो नकदी की उपलब्धता की आसान स्थिति और ऋण मांग में कमी आने को प्रदर्शित करती है। भारित औसत ऋण दर (डब्ल्यूएएलआर) में मामूली गिरावट हुई है जो बैंकों की दुर्बल मूल्य निर्धारण क्षमता को सूचित करती है जिसका आंशिक कारण परिसंपत्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताएं हैं जो बैंकों को उच्च जोखिम प्रीमियम वसूल करने के लिए प्रेरित करती हैं।

3.10 वर्ष 2007 के दौरान वास्तविक पॉलिसी ब्याज-दरें लगातार ऋणात्मक बनी रहीं (चित्र 3.5)। यह स्थिति 2013 अंत तक बदल गई जबकि वास्तविक ब्याज दरों में घनात्मक वृद्धि शुरू हुई और वर्तमान में ये दरें 2% से उच्च स्तर पर हैं (तिमाही अग्रदृष्टि आधार पर)।

सारणी 3.6 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) की जमा और ऋण दरें

मदें	औसत ब्याज दरें (%)				अंतर (प्रतिशतांक)
	मार्च 14	जून 14	सितंबर 14	15 दिसंबर 2014	मार्च की तुलना में दिसंबर में
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घरेलू सावधि जमा दरें - सभी परिपक्वता	7.69	7.65	7.62	7.54	-0.15
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	7.85	7.81	7.76	7.57	-0.28
निजी क्षेत्र के बैंक	7.67	7.57	7.56	7.50	-0.17
विदेशी बैंक	7.56	7.58	7.54	7.53	-0.03
				नव. 2014	मार्च की तुलना में नव. में
डब्ल्यूएएलआर (बकाया ऋण, रु. में) अनु.वा. बैंक	12.19	12.20	12.11	12.14	-0.05
डब्ल्यूएएलआर (नया ऋण, रु. में) अनु.वा. बैंक (एमसीबी)	11.64	11.68	11.59	11.60	-0.04

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी : एससीबी-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरआरबी-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डब्ल्यू एएलआर: भारित औसत ऋण दर डब्ल्यू एएलआर संबंधी आंकड़े अनंतिम है।

चित्र 3.5: वास्तविक पालिसी-दर (त्रैमासिक अग्र दृष्टि आधार पर)

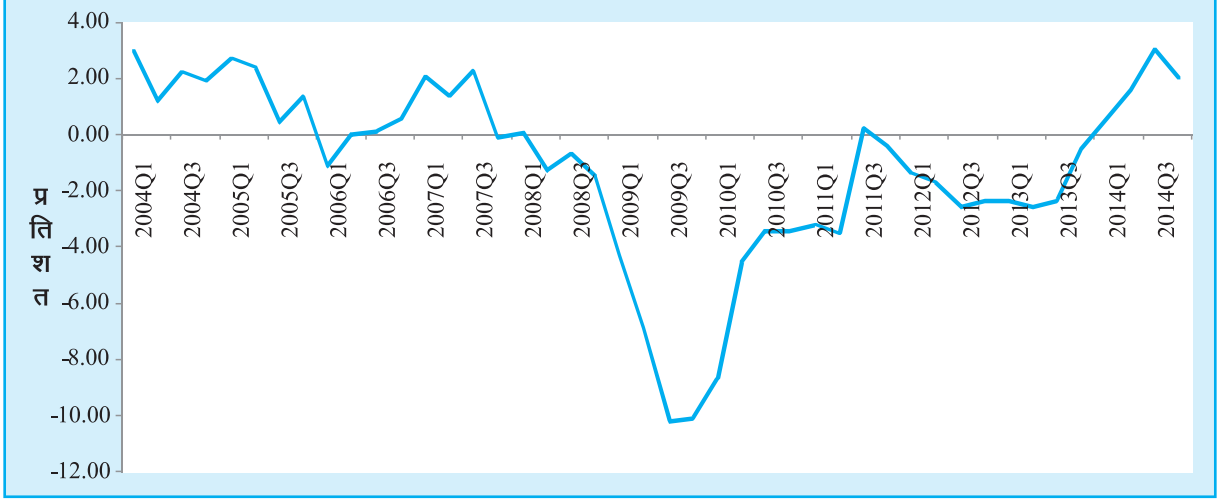

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कार्य निष्पादन

3.11 मार्च 2014 (आधार स्तर-पप्प) के अंत में प्रणाली स्तर पर पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 13.02 प्रतिशत था। सितंबर 2014 में यह अनुपात घटकर 12.75 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2015 में पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात की विनियामक अपेक्षा 9% है। तथापि, सकल राशि के स्तर पर पूंजी में गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी स्थिति खराब होने के कारण हुई। जबकि सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएएम) 12.75 प्रतिशत था, किंतु इससे आगे जाने पर बैंकिंग सेक्टर और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अतिरिक्त पूंजी कोष के संदर्भ में विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होगी।

3.12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता हाल के समय में दबाव में आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (दिसंबर, 2014) के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की कुल सकल अग्रिम राशियों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक अग्रिम राशियां मार्च 2014 के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2014 में 4.5 प्रतिशत हो गईं। बलित अग्रिम राशियां मार्च और सितंबर 2014 के बीच के 10.0 प्रतिशत से बढ़कर कुल अग्रिम राशियों का 10.7 प्रतिशत हो गई। जून, 2014 की स्थिति के अनुसार पांच उप क्षेत्रकों अर्थात अवसंरचना, लोहा एवं इस्पात, वस्त्र, खनन (कोयला सहित), और विमानन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बलित अग्रिम राशि की 54% राशि लगी हुई थी। सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार अवसंरचना के प्रति बैंक समूहों में से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण जोखिम उनकी सकल अग्रिम राशि का 17.5% था। यह निजी क्षेत्र के बैंकों (9.6%) और विदेशी बैंको (12.1%) की तुलना में पर्याप्त उच्च आंकड़ा था। दबाव परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि बृहत आर्थिक दशाओं में प्रत्याशित सकारात्मक घटनाओं के अंतर्गत बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में निकट भविष्य में सुधार हो सकता है और बैंक अपने प्रावधानों के मौजूदा स्तर पर प्रत्याशित हानि को पूरा करने की स्थिति में होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विगत में प्रदान किए गए ऋण के कारण दबाब में बने रहेंगे। सकल अनर्जक आस्तियों जीएनपीए तथा पुनर्गठित अग्रिम राशियों को एक साथ रखने पर सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबाब कुल अग्रिम राशियों का 12.57% है।

3.13 भारतीय रिजर्व बैंक ने अनर्जक आस्तियों से संबंधित मुद्दे का समाधान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जनवरी 2014 में ''वित्तीय कठिनाइयों को शीघ्र अभिज्ञात करने, ऋणदाताओं की समस्याओं के समाधान और निष्पक्ष वसूली हेतु शीघ्र उपाय: अर्थव्यवस्था में कठिनाई में स्थित आस्तियों के पुन: प्रवर्तन हेतु ढांचा'' के संबंध में इसने एक दिशानिर्देश जारी किए जिसमें उधार लेने वाले व्यक्ति के कार्यों में उसके दबाव पर होने की सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद बैंकों को कार्रवाई शुरू करनी होगी और बैंक इसके अनर्जक अस्ति (एनपीए) होने की प्रतीक्षा न करे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा और नई दोनों प्रकार की अवसंरचना और प्रमुख उद्योग परियोजनाओं के लिए परियोजना ऋणों में लोच लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। असहयोग कर रहे उधार प्राप्तकर्ताओं से वसूली की पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 2014 में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) के लिए मानदंडों को कड़ा किया है जिसमें प्रतिभूति प्राप्तियों में न्यूनतम निवेश 15% होना चाहिए जबकि पहले यह मानदंड 5% का था।

वित्तीय समावेशन

3.14 वित्तीय समावेशन सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसका उद्देश्य विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे कि बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण तक पहुंच, विप्रेषण सुविधा, समाज के वंचित वर्गों अर्थात् कमजोर तबकों और निम्न आय समूहों के लिए बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

3.15 **प्रधानमंत्री जनधन योजना:** देश के अब तक बड़ी संख्या में वंचित लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने और इसके विकसित होने की संभावनाओं को विस्तार प्रदान करने के लिए 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत बैकिंग सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाने की परिकल्पना की गई है जिसमें प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय सक्षमता, ऋण और बीमा तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई है। लाभभोगी को एक रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा अंतर्निहित होगा। इसके अतिरिक्त, 15 अगस्त, 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार अपना खाता खुलवाने वाले तथा योजना की पात्रता संबंधी अन्य शर्तों को पूरा करने वालों के लिए 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को वित्तीय अभियान के हिस्से के रूप में 23 अगस्त,

2014 के सप्ताह के दौरान सर्वाधिक बैंक खाता खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल किया गया है। 28 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, 12.31 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं जिनमें से 7.36 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.95 करोड़ खाते शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। पीएमजेडीवाई के अन्तर्गत 28 जनवरी 2015 की स्थिति के अनुसार 67.5 प्रतिशत खातों में शेष शून्य है। बैंकिग क्षेत्र में किए गए प्रमुख उपाय बाक्स 3.1 में दिए गए हैं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

3.16 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनवीएफसी) ने विशेषरूप से लघु तथा खुदरा क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती वित्तीय संस्था विकसित की है। एनवीएफसी ने पूर्ण रूप से (31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार) बैंक की परिसम्पत्तियों में 13.1 प्रतिशत तथा बैंक जमाराशियों में 0.2 प्रतिशत हिस्सेदारी की। एनवीएफसी को उनके सार्वजनिक रूप से जमा राशि को आधार बनाकर, अर्थात क्या वह सार्वजनिक रूप से जमा राशि ग्रहणकर्ता (एनवीएफसी-डी) है या नहीं (एनवीएफसी-एनडी) दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वृहत आकार वाली एनवीएफसी के पादुर्भाव के साथ व्यवस्थात्मक रूप से महत्वपूर्ण एनवीएफसी (जमा न करने वाले) अर्थात जिनके पास 500 करोड़ रुपए व उससे अधिक की परिसम्पत्तियां हैं, पर इस विनियामक केन्द्र बिन्दु में निरंतर वृद्धि हुई है। आरवीआई के साथ पंजीकृत कुल एनवीएफसी (30 सितम्बर 2013 की स्थिति अनुसार) 12,158 से कम होकर (30 सितम्बर 2014 की स्थिति अनुसार) 11,932 रह गए। एनवीएफसी-डी की संख्या 253 से कम होकर 226 रह गई है जबकि 100 करोड़ तथा उससे अधिक की परिसम्पत्ति वाले एनवीएफसी-एनडी की संख्या उसी अवधि में 437 से बढ़कर 465 हो गई थी। 30 सितम्बर 2014 की स्थिति के अनुसार, व्यवस्थात्मक रूप से महत्वपूर्ण एनवीएफसी (एनवीएफसी-एनडी-एसआई) की संख्या 200 थी। वर्ष 2013-14 के दौरान एनवीएफसी द्वारा लिए गए ऋण तथा अग्रिम में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। निधियों को प्रयोग में लाने के दृष्टिकोण से ऋण और अग्रिम निधियों के प्रयोग का दो तिहाई हिस्सा बैठता है।

3.17 आरबीआई ने नवम्बर 2014 में एन वी एफ सी हेतु एक संशोधित रूपरेखा जारी की है। चूंकि वे तीव्रगति से प्रतिपक्ष असफलताओं, निधियन और परिसम्पत्ति संकेन्द्रण, ब्याज दर में घट-बढ़ और नकदी तथा ऋण चुकाने संबंधी जोखिमों का पर्दाफाश कर रहे है।

पूंजी बाजार में घटनाक्रम

प्राथमिक बाजार

3.18 अप्रैल-दिसम्बर 2014 के अनुसार प्राथमिक बाजार के माध्यम से संसाधन जुटाने से इक्विटी और ऋण में गिरावट के मामलों तथा वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ते निजी नियोजनों से मिश्रित पद्धति प्रदर्शित हुई है। क्योंकि निजी नियोजन एक

बॉक्स 3.1 : बैंकिंग सेक्टर की प्रमुख पहलें

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के नए बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु 22 फरवरी 2013 को दिशा निर्देश जारी किए जिसके परिणामस्वरूप दो आवेदकों को 18 महीने की अवधि के भीतर निजी क्षेत्र में नए बैंकों को खोलने के लिए अप्रैल 2014 में ''सिद्धांत रूप में'' अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) विशिष्ट हितों को पूरा करने के लिए विशिष्ट बैंकों, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों, भुगतान बैंकों, आदि को स्थापित करने के संबंध में 2014-15 की बजट घोषणा के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए और नवंबर 2014 में उन्हें जारी कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे बैंको और भुगतान बैंको को स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।

(ग) भुगतान तथा निपटान पद्धति (संशोधन) विधेयक 2014: भुगतान तथा निपटान पद्धति अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) का अधिनियमन भारत में भुगतान प्रणाली के आरबीआई द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु एक ठोस कानूनी आधार उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया था। व्यापार निक्षेपगारों और कानूनी निकाय अभिज्ञात निर्गमकर्ताओं के विनियमन हेतु कानूनी ढांचा स्थापित करने के लिए पीएसएस अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इस अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक समझा गया। प्रस्तावित संशोधन एक केंद्रीय विरोधी पक्ष (पद्धति प्रदाता) और पद्धति में भाग लेने वालों के बीच केंद्रीय विरोधी पक्ष के दिवालियापन, विघटन या उसके समाप्त होने की स्थिति में भुगतान देयताओं के निर्धारण और निपटान हेतु अनुदेशों को अंतिम रूप प्रदान करेगा। इस विधेयक लोकसभा द्वारा वर्ष 2014 के शीतकालीन सत्र में पारित कर दिया गया है तथा फिलहाल यह विधेयक राज्य सभा में लंबित है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत आवश्यकता: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10 दिसम्बर 2014 को चरणबद्ध रूप से सरकारी शेयरधारिता को 52 प्रतिशत तक कम करते हुए एफपीओ अथवा क्यूआईपी के जरिए सार्वजनिक बाजारों से पूंजी जुटाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनकी पूंजीगत आवश्यकता, उनके स्टॉक निष्पादन, नकदी, बाजार प्रवृत्ति तथा ऐसी अन्य स्थितियों के अध्यधीन अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

सारणी 3.7 : प्राथमिक बाजार में संसाधन जुटाया जाना (करोड़ रुपए)

	2012-13	2013-14	2013-14#	2014-15#
ऋण	16982	42383	17436	7348
इक्विटी	15473	13269	8124	4292
जिनमें से आईपीओ	6528	1236	1166	1480
कारपोरे बांडों का निजी स्थापन	361462	276054	201838	269245
कुल	**393917**	**331706**	**227398**	**280885**

स्रोत : सेबी

टिप्पणी : वे इक्विटी निर्गम जिन पर विचार किया गया था केवल इक्विटी सार्वजनिक निर्गम है।

संबंधित वर्ष के 31 दिसम्बर को इंगित करता है।

बड़ा हिस्सा है, इस अवधि में जुटाई गई कुल राशि में बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि के दौरान एन एस ई तथा बी एस ई दोनों में निजी नियोजन की संख्या और महत्व बढ़ा है। (सारणी 3.7)

द्वितीयक बाजार

3.19 चालू वर्ष में अभी तक बेंचमार्क सूचकांकों बीएसई सेनसेक्स और निफ्टी में वर्षानुवर्ष (आंकड़े) 31.4 और 29.9 प्रतिशत तक तदनुरूप वृद्धि दरों के साथ 31 दिसम्बर 2014 को क्रमश: 27,499.4 और 8283 पर समाप्त होते हुए सामान्य बढ़त की प्रवृति देखी गई थी (चित्र 3.6)। भारतीय सूचकांक विश्व के बेहतर प्रदर्शन सूचकांकों में है (सारणी 3.8)।

चित्र 3.6: निफ्टी और सेनसेक्स के सूचकांकों में घट-बढ़

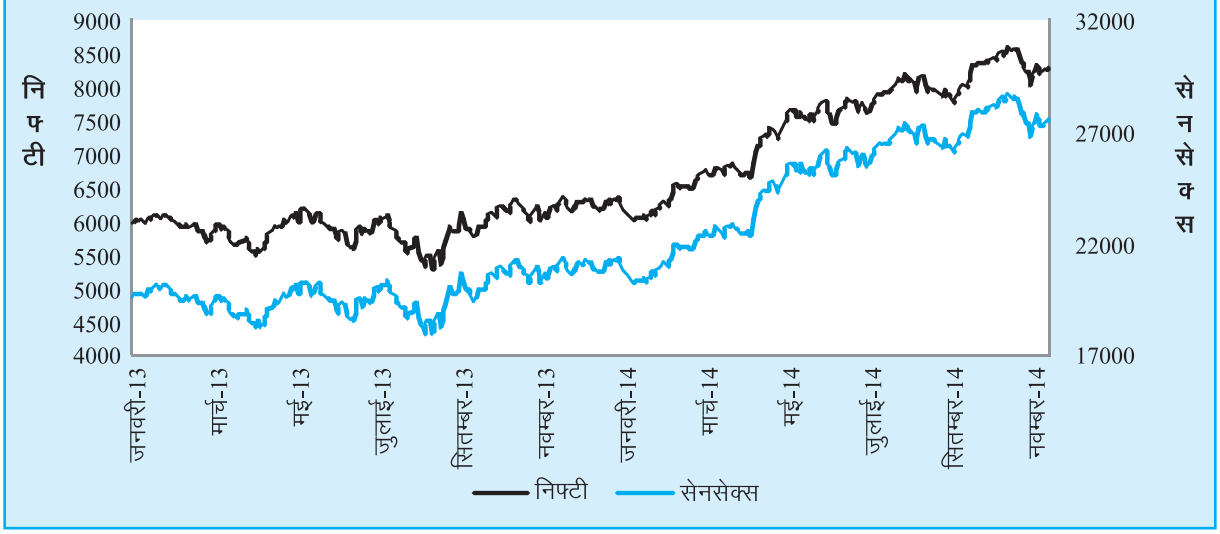

सारणी 3.8 : विश्व के प्रमुख स्टॉक बाजारों का प्रदर्शन

सूचकांक	देश	सूचकांक मूल्य 2014#	2013 की तुलना में 2014 में प्रतिशत परिवर्तन (स्थानीय मुद्रा आधारित)	2013 की तुलना में 2014 में प्रतिशत परिवर्तन (अमकीकी डालर की दर पर)
सेंसेक्स	भारत	27499	29.9	27.1
निफ्टी	भारत	8283	31.4	28.5
एसपीएक्स	यूएसए	2059	11.4	11.4
डीएएक्स	जर्मनी	9806	2.7	-9.6
यूकेएक्स	इंगलैण्ड	6566	-2.7	-8.5
एनकेवाई	जापान	17451	7.1	-5.8
एचएसआई	हांगकांग	23605	1.3	1.3
आइबीओवी	ब्राजील	50007	-2.9	-13.4
कोस्पी	कोरिया	1916	-4.8	-8.4
एफएसएसटीआई	सिंगापुर	3365	6.2	1.2
एसएचसीओएमपी	चीन	3235	52.9	49.1
सीएसी	फ्रांस	4273	-0.5	-12.7

स्रोत : ब्लूमबर्ग

टिप्पणी : # संबंधित वर्ष के 31 दिसम्बर की स्थिति दर्शाता है।

सारणी 3.9 : मुद्रा और ब्याज दर व्युत्पन्न (करोड़ रुपए में)

एक्सचैंज	मुद्रा व्युत्पन्न में व्यापार मूल्य		ब्याज दर व्युत्पन्न में व्यापार मूल्य	
	2013-14#	2014-15#	2013-14#	2014-15#
एनएसई	3454979	2101567	30173	266607
एमसीएक्स-एसएक्स	2166528	534329	7191	20346
यू एस ई	185385	52185		
बी एस ई	17552	1073916	2580	1440

स्रोत : एनएसई, एमसीएक्स-एसएक्स, बी एस ई और यू एस ई।

टिप्पणी : # संबन्धित वर्ष के 31 दिस्म्बर को इंगित करता है।

3.20 **मुद्रा और ब्याज दर व्युत्पन्न:** मुद्रा व्युत्पन्न खण्ड (सारणी 3.9) में व्यापार में अधिकांश मुद्राओं में गिरावट देखी गई। जनवरी 2014 से 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर व्यापार में भावी संविदाओं में नकद आधारित ब्याज दर आरम्भ की गयी

3.21 **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश:**1 जून 2014 से एफ पी आई व्यवस्था की शुरूआत के साथ, पूर्व एफ आई आई, उप-खातों तथा क्यू एफ आई को मिलाकर निवेशकों की एक नई श्रेणी ''विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक'' बनाई गई है। अप्रैल-दिसम्बर 2014 के दौरान कुल निवल एफ पी आइ अन्तर्वाह वर्ष 2013-14 की तदनुरूप अवधि में 539 मिलियन अमरीकी डालर के बहिर्वाह की तुलना में 32,943 मिलियन अमरीकी डालर था।

वर्ष के दौरान प्राथमिक और द्वितीय दोनों बाजारों के विकास के लिए सेबी ने अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। प्रमुख नीतिगत घटनाक्रम बॉक्स 3.2 में दिए गए हैं।

बीमा क्षेत्र

3.22 भारत में बीमा प्रवेश वर्ष 2000 में 2.3 प्रतिशत (जीवन में 1.8 प्रतिशत तथा तथा गैर-जीवन 0.7 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2013 में 3.9 प्रतिशत (जीवन 3.1 प्रतिशत तथा गैर-जीवन 0.8 प्रतिशत हो गया है। जीवन बीमा प्रवेश स्तर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के साथ कदम मिलाए हुए है। वर्ष 2013-14 के दौरान, जीवन बीमा उद्योग ने 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वित्त वर्ष में 2,87,202 करोड़ रुपए के मुकाबले 3,14,283 करोड़ रुपए की प्रीमियम आय दर्ज की है। जबकि निजी क्षेत्र के बीमा कर्ताओं ने अपनी प्रीमियम आय में 1.4 प्रतिशत की गिरावट दर्शाई है। जीवन बीमा निगम ने इस अवधि में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कुल प्रीमियम आय के आधार पर, एलआईसी का बाजार हिस्सा वर्ष 2012-13 में 72.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 75.4 प्रतिशत हो गया था।

3.23 बीमा कानूनो में अप्रचलित तथा अनावश्यक उपबंध ों को ध्यान में रखते हुए एक भारतीय बीमा कंपनी में भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण के साथ विदेशी इक्विटी निवेश सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करके तथा और अधिक प्रभावशाली विनियमन में इर्डा को समर्थ बनाने के लिए सशक्त किया गया है। सरकार ने 26 दिसम्बर 2014 को बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2014 की घोषणा की है। इस अध्यादेश से बीमा अधिनियम, 1938, सामान्य बीमा कार्य (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन किया जाएगा।

पेंशन क्षेत्र

3.24 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जो आरंभ में एक जनवरी 2004 को केन्द्रीय सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों (पहले चरण में सैन्य दल को छोड़कर) के लिए शुरू की गई थी बाद में स्वायत्त निकायों/राज्य सरकारों तथा असंगठित क्षेत्रों के लिए भी इसका विस्तार कर दिया गया। दो राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्य 1 मई 2009 से राष्ट्रीय पेंशन योजना की परिधि में आ गए हैं। इस राष्ट्रीय पेंशन योजना को भारत के सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर अपनाने के मार्ग खोले गए हैं। 31 दिसम्बर, 2014 तक इस राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 73,097 करोड़ रुपए की निधि के साथ कुल 79.71 लाख सदस्यों को इस योजना के अंतर्गत नामांकित किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियों में 49.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.3.2014 में 48,136 करोड़ से 31 दिसम्बर, 2014 में 72,000 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी गई है।

बॉक्स 3.2: नीतिगत घटनाक्रम (अप्रैल-दिसम्बर, 2014)

प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम 2014: अगस्त 2014 में पारित इस अधिनियम द्वारा सेवी द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का विस्तार किया गया जिनमें शामिल है: गलत तरीकों से उठाए गए लाभ समाप्त करने जांच करवाने तथा उसे जब्त करने संबंधी सुस्पष्ट शक्तियां, प्रतिस्थापन, संयोजन और वसूली हेतु स्पष्ट शक्तियां, शास्तियां बढ़ाना, विशेष न्यायालयों की स्थापना आदि।

प्राथमिक बाजार

- कारपोरेट अधिशासन मापदण्डों को सुदृढ़ करने के लिए सेबी ने इक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 49 में संशोधन किया है, जिसमें व्यवस्था की गई है कि नामित निदेशक को स्वतंत्र निदेशक अनिवार्यत: संचेतक तंत्र आदि की परिभाषा से अलग रखा जाएगा।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली 1957 में तीन वर्ष के भीतर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जारी कुल शेयरों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सरकारी शेयरधारिता अनिवार्य करने के लिए संशोधान किया गया।

द्वितीयक बाजार

- 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति वाली नकद आधारित भावी ब्याज दर की शुरूआत करने के लिए स्टाक एक्सचेन्ज की संरचना निधरित की गई थी।
- निबंधन और शर्तों के अध्यधीन मुद्रा व्युत्पन्न में व्यापार करने के लिए एफ पी आई की अनुमति दी गई।
- सेबी ने निक्षेपागारों के साथ डिमेट फॉर्म में धारित म्यूचुअल फण्डों और प्रतिभूतियों में एक निवेशक के सभी प्रभार के निवेशों के लिए एक एकल समेकित दृष्टिकोण बनाया
- सेबी ने स्टाक ब्रोकर/क्लीयरिंग मेम्बर के लिए एक ही बार पंजीकृत होने की अनुमति दी। दोनों तरह के निक्षेपगारों को संचालित करने के लिए एकल पंजीयन प्रदान करने की नीति को मंजूरी प्रदान की गई।
- सेबी ने अन्य विनियामकों के साथ अपने ग्राहक की जानकारी सांझा करने के लिए सेवी (केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेन्सी) (केआरए) विनिमय 2011 में संशोधन किया।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

- यह सेवी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) विनियम, 2014, 1 जून 2014 से लागू किया गया। पदनामित निक्षेपागार भागीदार (डीडीपी) के लिए कार्यान्वयनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- अप्रैल 2014 से, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई/क्यूएफआई निवेशों के लिए निवेश स्थितियों में बदलाव किया गया, जिसके द्वारा टी-बिल में उनके निवेशों को परिपक्वता अवधि/विक्री के संबंध में कम करने की अनुमति दी गई।
- एफपीआई को एक भारतीय कंपनी तथा प्रसिद्ध भारतीय स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी किए गए डिवेन्चर्स अथवा गैर-परिवर्तनीय/विमोचन योग्य अधिमान शेयर को देश में प्रत्यवर्तन आधार पर निवेश करने की अनुमति दी गई

म्युचुअल फण्ड कारपोरेट बॉण्डस, एआईएफ

- सितम्बर 2014 में सेबी (स्थावर संपदा निवेश न्यास) विनियम 2014 अधिसूचित किए गए।
- सितम्बर, 2014 में सेबी ने आधारभूत संरचना निवेश न्यास विनियम अधिसूचित किए जो भारत में एआईफ के पंजीकरण और विनियमन के लिए कार्यढांचा मुहैया कराते हैं।
- सेबी (अनुसंधान विश्लेषण) विनियम 2014, 1 सितम्बर, 204 को अधिसूचित किया गया।

स्वावलंबन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में पेंशन के लिए वर्ष 2010 में आरंभ की गई सह-अंशदायी पेंशन योजना अब भारत के उन सभी नागरिकों के लिए भी खोली गई है जो किसी पेंशन/भविष्य निधि योजना के भाग नहीं है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 31 दिसम्बर, 2014 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 6.29 लाख अंशदाता पहले ही नामांकित कर लिए गए हैं।

3.25 पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम 2013 को सितम्बर, 2013 में संसद द्वारा पारित किए जाने के उपरांत 01 फरवरी 2014 से प्रभावी बना दिया गया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 में पीएफआरडीए को संवैधानिक स्तर की जिम्मेदारी देने का प्रयास है ताकि इस स्तर से वह अपनी विनियामक और विकासशील भूमिका को कारगर तरीके से निभा सके।